मोनेटरी एंड क्रेडिट इन्फॉर्मेशन रिव्यू

खण्ड XIX अंक 4 जुलाई 2023

एमसीआईआर

विषयवस्तु

खंड	पृष्ठ
I. विनियमन	1
II. भुगतान और निपटान प्रणाली	2
III. मुद्रा प्रबंधन	2
IV. वित्तीय बाजार	2
V. ऋण प्रबंधन	2
VI. वर्किंग पेपर और रिपोर्ट	3
VII. सर्वेक्षण	3-4
VIII. प्रकाशन	4
IX. जारी आंकड़े	4

संपादक की कलम से

मोनेटरी एवं क्रेडिट इंफर्मेशन रिव्यू (एमसीआईआर) के एक और संस्करण में आपका स्वागत है। रिज़र्व बैंक की यह मासिक आवधिक पत्रिका धन और ऋण की दुनिया में रिज़र्व बैंक द्वारा जुलाई 2023 माह के दौरान किए गए नए विकास और महत्वपूर्ण नीतिगत पहलुओं के साथ जुड़े रहने में आपकी मदद करती है। एमसीआईआर को https://mcir.rbi.org.in पर और साथ ही क्यूआर कोड को स्कैन करके देखा जा सकता है।

संवाद के इस माध्यम से सूचनाएं साझा करने, शिक्षित करने और आप सबसे जुड़े रहने के साथ हमारा उद्देश्य यह सुनिश्चित करना भी है कि प्रसारित की जा रही सूचनाओं में तथ्यात्मक सटीकता एवं संगति रहे।

हम आपकी प्रतिक्रिया का mcir@rbi.org.in पर स्वागत करते हैं।

योगेश दयाल
संपादक

I. विनियमन

गवर्नर की सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के बैंकों के एमडी और सीईओ के साथ बैठक

श्री शक्तिकान्त दास, गवर्नर, भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 11 जुलाई 2023 को मुंबई में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों और चुनिंदा निजी क्षेत्र के बैंकों के एमडी और सीईओ के साथ बैठकें कीं। बैठकों में उप गवर्नर, श्री एम. राजेश्वर राव और श्री स्वामीनाथन जे. के साथ-साथ भारतीय रिज़र्व बैंक के कुछ वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल हुए।

गवर्नर ने अपनी परिचयात्मक टिप्पणी में विभिन्न प्रतिकूल वैश्विक घटनाक्रमों के बावजूद, भारतीय बैंकिंग प्रणाली के अच्छे कार्य-निष्पादन का उल्लेख करते हुए इस बात पर ज़ोर दिया कि ऐसे समय में बैंकों को अतिरिक्त सावधानी बरतने और सतर्क रहने की जरूरत है। गवर्नर ने इस बात पर भी ज़ोर दिया कि एमडी और सीईओ को बैंकों में सुशासन को सुदृढ़ करने और अनुपालन, जोखिम प्रबंधन और लेखा-परीक्षा कार्यों से युक्त बैंकिंग स्थिरता के तिपाई (ट्राइपॉड) पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है।

ऋण हामीदारी मानकों को मजबूत करने, बृहद एक्सपोज़र की निगरानी करने, बाह्य बेंचमार्क संबद्ध दर (ईबीएलआर) दिशानिर्देशों के कार्यान्वयन, आईटी सुरक्षा और आईटी सुशासन को सुदृढ़ करने, बट्टे खाते में डाले गए खातों से वसूली में सुधार और साख सूचना कंपनियों के साथ समय पर और सटीक जानकारी साझा करने से संबंधित मुद्दे पर चर्चा की गई। विस्तार से पढ़ने के लिए कृपया यहाँ क्लिक करें।

भारतीय रिज़र्व बैंक और सेंट्रल बैंक ऑफ यूएई के बीच सहमति ज्ञापन

रिज़र्व बैंक और सेंट्रल बैंक ऑफ यूएई (सीबीयूएई) ने 15 जुलाई 2023 को आबू धाबी में

i) सीमापारीय लेनदेन के लिए स्थानीय मुद्राओं अर्थात्, भारतीय रुपया (आईएनआर) और संयुक्त अरब अमीरात दिरहम (एईडी) के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए एक रूपरेखा तैयार करने; और

ii) अपने भुगतान और मैसेजिंग प्रणाली की आपसी सहबद्धता हेतु सहयोग के लिए दो सहमति ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए।

सहमति ज्ञापनों पर भारतीय रिज़र्व बैंक के गवर्नर श्री शक्तिकान्त दास और सेंट्रल बैंक ऑफ यूएई के गवर्नर एच.ई. खालिद मोहम्मद बलामा द्वारा हस्ताक्षर किए गए। भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति महामहिम शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान की गरिमामय उपस्थिति में, दोनों गवर्नरों के बीच सहमति ज्ञापनों का आदान-प्रदान किया गया।

भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच लेनदेन के लिए स्थानीय मुद्राओं के उपयोग हेतु एक रूपरेखा तैयार करने संबंधी सहमति ज्ञापन का उद्देश्य, द्विपक्षीय रूप से आईएनआर और एईडी के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए एक स्थानीय मुद्रा निपटान प्रणाली (एलसीएसएस) स्थापित करना है। एमओयू सभी चालू खाता लेनदेन और अनुमत पूंजी खाता लेनदेन को शामिल करता है। एलसीएसएस के निर्माण से निर्यातक और आयातक अपनी संबंधित घरेलू मुद्राओं में चालान तैयार करने और भुगतान करने में सक्षम होंगे, जो बदले में आईएनआर-एईडी विदेशी मुद्रा बाजार के विकास को सक्षम करेगा। इस व्यवस्था से दोनों देशों के बीच निवेश और विप्रेषण को भी बढ़ावा मिलेगा। स्थानीय मुद्राओं का उपयोग लेनदेन लागत और लेनदेन के निपटान समय को अनुकूलित करेगा, जिसमें संयुक्त अरब अमीरात में रहने वाले भारतीयों से विप्रेषण भी शामिल होगा।

'भुगतान और मैसेजिंग प्रणाली' संबंधी एमओयू के अंतर्गत, दोनों केंद्रीय बैंक

ए) अपने त्वरित भुगतान प्रणाली (एफपीएस) - भारत के यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (यूपीआई) को यूएई के इंस्टेंट पेमेंट प्लेटफॉर्म (आईपीपी) की सहबद्धता;

बी) संबंधित कार्ड स्विच (रुपे स्विच और यूएईस्विच) की सहबद्धता; और

सी) संयुक्त अरब अमीरात में मैसेजिंग सिस्टम के साथ भारत के भुगतान मैसेजिंग सिस्टम अर्थात्, स्ट्रक्चर्ड फाइनेंशियल मैसेजिंग सिस्टम (एसएफएमएस) की सहबद्धता का पता लगाने हेतु सहयोग करने के लिए सहमत हुए।

यूपीआई-आईपीपी सहबद्धता, दोनों देशों के उपयोगकर्ताओं को तीव्र, सुविधाजनक, सुरक्षित और किफ़ायती सीमापारीय धन अंतरण करने में सक्षम बनाएगा। कार्ड स्विचों की सहबद्धता से घरेलू कार्डों की पारस्परिक स्वीकृति और कार्ड लेनदेन के प्रसंस्करण में सुविधा होगी। मैसेजिंग सिस्टम की सहबद्धता का उद्देश्य दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय वित्तीय मैसेजिंग को सुविधाजनक बनाना है। विस्तार से पढ़ने के लिए कृपया यहाँ क्लिक करें।

पंजीकरण प्रमाणपत्र

भारतीय रिज़र्व बैंक ने 13 जुलाई 2023 को भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए (6) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए चार गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफ़सी) का पंजीकरण प्रमाणपत्र निरस्त कर दिया।

इसके अलावा 13 जुलाई 2023 को ग्यारह एनबीएफ़सी ने भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा उन्हें जारी किए गए पंजीकरण प्रमाणपत्र का अभ्यर्पण किया। अत: रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए (6) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उनके पंजीकरण प्रमाणपत्र को निरस्त कर दिया। विस्तार से पढ़ने के लिए कृपया यहाँ क्लिक करें।

II. भुगतान और निपटान प्रणाली

कार्ड नेटवर्क के साथ व्यवस्था

रिज़र्व बैंक ने 5 जुलाई 2023 को डेबिट, क्रेडिट और प्रीपेड कार्ड जारी करने के लिए कार्ड नेटवर्क के साथ व्यवस्था संबंधी ड्राफ्ट परिपत्र को हितधारकों की प्रतिक्रिया हेतु अपनी वेबसाइट पर रखा।

ड्राफ्ट परिपत्र कार्ड जारीकर्ताओं (बैंकों/ गैर-बैंकों) को एक से अधिक कार्ड-नेटवर्क पर कार्ड जारी करने के साथ-साथ ग्राहकों को बहुविध कार्ड नेटवर्क में से किसी एक को चुनने की सुविधा प्रदान करने का आदेश देता है। यह कार्ड जारीकर्ताओं को ऐसे करार करने से भी रोकता है जो अन्य कार्ड-नेटवर्क के साथ संबद्ध होने की उनकी क्षमता को सीमित करते हैं। विस्तार से पढ़ने के लिए कृपया यहाँ क्लिक करें।

डिजिटल भुगतान सूचकांक

रिज़र्व बैंक ने 27 जुलाई 2023 को मार्च 2023 के लिए डिजिटल भुगतान सूचकांक (डीपीआई) जारी किया। यह सूचकांक 395.57 रहा, जबकि सितंबर 2022 के लिए यह 377.46 था, जिसकी घोषणा 31 जनवरी 2023 को की गई थी।

हाल के वर्षों में देश भर में भुगतान अवसंरचना और भुगतान निष्पादन में महत्वपूर्ण वृद्धि के कारण आरबीआई-डीपीआई सूचकांक सभी मापदंडों में बढ़ा है।

अपने आरंभ से सूचकांक शृंखला निम्नानुसार है:

अवधि	आरबीआई-डीपीआई सूचकांक
मार्च 2018 (आधार)	100
मार्च 2019	153.47
सितंबर 2019	173.49
मार्च 2020	207.84
सितंबर 2020	217.74
मार्च 2021	270.59
सितंबर 2021	304.06
मार्च 2022	349.30
सितंबर 2022	377.46
मार्च 2023	395.57

विस्तार से पढ़ने के लिए कृपया यहाँ क्लिक करें।

III. मुद्रा प्रबंधन

₹2000 के बैंकनोटों की स्थिति

रिज़र्व बैंक ने 1 अगस्त 2023 को ₹2000 मूल्यवर्ग के बैंकनोटों को वापस लेने की स्थिति जारी की। बैंकों से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार, 19 मई 2023 को ₹2000 के बैंकनोटों को संचलन से वापस लेने की घोषणा के बाद से 31 जुलाई 2023 तक संचलन से वापस प्राप्त ₹2000 के बैंक नोटों का कुल मूल्य ₹3.14 लाख करोड़ है। परिणामस्वरूप, 31 जुलाई 2023 को कारोबार की समाप्ति पर संचलन में ₹2000 के बैंक नोट का मूल्य ₹0.42 लाख करोड़ था। इस प्रकार, 19 मई 2023 को संचलन में मौजूद ₹2000 के बैंकनोटों में से 88 प्रतिशत वापस आ गए हैं। प्रमुख बैंकों से एकत्र किए गए आंकड़ों से पता चलता है कि संचलन से वापस प्राप्त ₹2000 मूल्यवर्ग के कुल बैंकनोटों में से लगभग 87% जमाराशि के रूप में प्राप्त किए गए और शेष लगभग 13% को अन्य मूल्यवर्ग के बैंकनोटों में बदला गया। विस्तार से पढ़ने के लिए कृपया यहाँ क्लिक करें।

तारांकित शृंखला वाले बैंकनोट

रिज़र्व बैंक ने दिनांक 27 जुलाई 2023 को प्रेस प्रकाशनी के माध्यम से स्पष्ट किया कि तारा (*) चिह्न ऐसे बैंकनोट की संख्या पटल पर अंकित किया जाता है, जिसका उपयोग क्रमांकित बैंकनोटों के 100 नगों वाले पैकेट में दोषपूर्ण मुद्रित बैंकनोटों के प्रतिस्थापन के रूप में किया जाता है। तारा (*) चिन्ह वाला बैंकनोट किसी भी अन्य वैध बैंकनोट के समान होता है, सिवाय इसके कि संख्या पटल के शुरुआत (प्रिफिक्स) और क्रम संख्या के बीच एक तारा (*) चिन्ह अंकित किया जाता है। तारा (*) चिन्ह एक पहचान चिन्ह है कि यह बैंकनोट एक प्रतिस्थापित/ पुनः मुद्रित बैंकनोट है। "तारांकित शृंखला" वाले बैंकनोटों के बारे में जानकारी भारतीय रिज़र्व बैंक की वेबसाइट पर भारतीय मुद्रा (खंड बी के प्रश्न 9) पर अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न के भाग के रूप में उपलब्ध है। विस्तार से पढ़ने के लिए कृपया यहाँ क्लिक करें।

IV. वित्तीय बाज़ार

डेटा मदों की परिभाषा

रिज़र्व बैंक ने 17 जुलाई 2023 को 101 अतिरिक्त डेटा मदों की परिभाषाओं को शामिल करके विनियामक रिपोर्टिंग के लिए 'बैंकिंग सांख्यिकी- डेटा तत्वों की सामंजस्यपूर्ण परिभाषाएँ' संबंधी शब्दावली को अद्यतन किया। जब कभी विनियामक रिपोर्टिंग के लिए नए डेटा मद निर्धारित किए जाएंगे या किसी मौजूदा डेटा मद/ मदों के लिए स्पष्टीकरण/ संशोधन की आवश्यकता होगी तब इस शब्दावली को अद्यतन किया जाएगा। विस्तार से पढ़ने के लिए कृपया यहाँ क्लिक करें।

V. ऋण प्रबंधन

राज्य वित्त सचिवों का सम्मेलन

रिज़र्व बैंक ने 6 जुलाई 2023 को मुंबई में राज्य वित्त सचिवों का 33वां सम्मेलन आयोजित किया। इस सम्मेलन का विषय 'ऋण धारणीयता: राज्यों का परिप्रेक्ष्य' था और इसमें 23 राज्यों तथा एक संघ शासित प्रदेश के वित्त सचिवों तथा वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के अधिकारियों, महालेखा नियंत्रक और भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक ने भाग लिया। सम्मेलन का उद्घाटन श्री शक्तिकान्त दास, गवर्नर, भारतीय रिज़र्व बैंक ने किया। सम्मेलन को संबोधित करते हुए, गवर्नर ने राज्यों के दीर्घकालिक राजकोषीय स्वास्थ्य को सुनिश्चित करने के लिए ऋण धारणीयता के महत्व पर प्रकाश डाला। उन्होंने राज्यों को राजकोषीय सुदृढ़ीकरण, व्यय की गुणवत्ता में सुधार और राज्यों के राजकोषीय स्वास्थ्य से संबंधित अन्य मुद्दों यथा आकस्मिक देयताएँ/ गारंटी आदि पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता पर जोर दिया।

बैठक में अन्य बातों के साथ-साथ, राज्यों द्वारा बाज़ार उधार, समेकित ऋण-शोधन निधि और गारंटी उन्मोचन निधि का प्रबंधन, राज्य सरकार की गारंटी से संबंधित मुद्दे, भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा राज्यों को अल्पावधि वित्तीय निभाव आदि की समीक्षा की गई। विस्तार से पढ़ने के लिए कृपया यहाँ क्लिक करें।

VI. वर्किंग पेपर और रिपोर्ट

आरबीआई वर्किंग पेपर सं. 07/2023

रिज़र्व बैंक ने 4 जुलाई 2023 को अपनी वेबसाइट पर भारतीय रिज़र्व बैंक वर्किंग पेपर शृंखला के अंतर्गत "असंपार्श्विकीकृत एक दिवसीय दर के पद्धति-आधारित निर्धारक तत्व: परिचालन प्रक्रिया और बाजार माइक्रोस्ट्रक्चर के पारस्परिक प्रभाव" शीर्षक से एक वर्किंग पेपर जारी किया। पेपर का सह-लेखन एडविन प्रभु ए और इंद्रनील भट्टाचार्य ने किया है। पेपर के मुख्य निष्कर्ष निम्नानुसार हैं:

i) चलनिधि की स्थिति, बाजार सहभागियों की नीतिगत प्रत्याशाएँ, आरक्षित रखरखाव अवधि के भीतर अल्पकालिक ब्याज दर की प्रत्याशाएँ, संरचनात्मक चलनिधि और कॉरीडोर का दायरा, डब्ल्यूएसीआर द्वारा एलएएफ कॉरीडोर की ऊपरी सीमा को तोड़ने के कारण समझाने में महत्वपूर्ण थीं।

ii) आरक्षित रखरखाव अवधि के भीतर ब्याज दर प्रत्याशाएँ, नीति प्रत्याशाएँ और चलनिधि वितरण, डब्ल्यूएसीआर द्वारा एलएएफ कॉरीडोर की निचली सीमा को तोड़ने के कारण समझाने में महत्वपूर्ण पाए गए।

iii) औसत सीमांत प्रभावों के संदर्भ में रिपोर्ट किए गए परिणाम, दुर्लभ घटनाओं की उपस्थिति को ध्यान में रखते हुए भी मजबूत पाए गए। विस्तार से पढ़ने के लिए कृपया यहाँ क्लिक करें।

आरबीआई वर्किंग पेपर सं. 08/2023

भारतीय रिज़र्व बैंक ने 5 जुलाई 2023 को अपनी वेबसाइट पर भारतीय रिज़र्व बैंक वर्किंग पेपर शृंखला के अंतर्गत "पोर्टफोलियो प्रवाह और विनिमय दर अस्थिरता: ब्रिक्स देशों के लिए एक अनुभवजन्य आकलन" शीर्षक से एक वर्किंग पेपर जारी किया। पेपर का सह-लेखन दीपक आर. चौधरी, पुष्पा त्रिवेदी और प्रभात कुमार ने किया है।

यह पेपर जनवरी 2000 से जुलाई 2021 की अवधि के दौरान पांच ब्रिक्स मुद्राओं (ब्राज़ीलियाई रियल, रूसी रूबल, भारतीय रुपया, चीनी आरएमबी और दक्षिण अफ्रीकी रैंड) की विनिमय दर की अस्थिरता पर निवल इक्विटी और बॉण्ड पोर्टफोलियो अंतर्वाह के प्रभावों की जांच करता है। निष्कर्षों से पता चलता है कि बॉण्ड और इक्विटी बाजारों में पोर्टफोलियो प्रवाह इन मुद्राओं की विनिमय दर की अस्थिरता को प्रभावित करता है। बॉण्ड बाजार में या इक्विटी बाजार में पोर्टफोलियो प्रवाह से, ब्राजील को छोड़कर, ब्रिक्स मुद्राओं में मूल्यवृद्धि हुई। विस्तार से पढ़ने के लिए कृपया यहाँ क्लिक करें।

डीआरजी अध्ययन संख्या 49

भारतीय रिज़र्व बैंक ने 6 जुलाई 2023 को अपनी वेबसाइट पर "भारतीय सब्जी बाजार में कीमत अस्थिरता संचारण का गहन विश्लेषण" शीर्षक से डीआरजी अध्ययन जारी किया। इस अध्ययन का सह-लेखन पूजा पाढी, हिमानी शेखर और आकांक्षा हांडा द्वारा किया गया है।

अध्ययन तीन प्रमुख सब्जियों अर्थात्, टमाटर, प्याज और आलू (टीओपी) के लिए क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर अस्थिरता संचारण की जांच करता है। यह अध्ययन उपभोक्ता मामला विभाग (डीसीए) से प्राप्त जनवरी 2011 से मार्च 2021 की अवधि के दौरान इन सब्जियों की दैनिक थोक और खुदरा कीमतों पर आधारित है। अध्ययन के प्रमुख निष्कर्ष निम्नानुसार हैं:

i) सब्जियों में क्षैतिज कीमत अस्थिरता संचारण टमाटर से लेकर प्याज और आलू तक, खुदरा और थोक दोनों बाज़ारों में देखा जा सकता है।

ii) जबकि प्याज और टमाटर के मामले में थोक और खुदरा कीमतों के बीच अस्थिरता संचारण थोक से खुदरा कीमतों तक यूनिडायरेक्शनल (दिशाहीन) है, यह आलू के मामले में बाइ-डायरेक्शनल (द्वि-दिशात्मक) है, जो ऊर्ध्वाधर संचारण तंत्र को दर्शाता है।

iii) अध्ययन में थोक या खुदरा कीमतों में इन तीन सब्जियों में सकारात्मक या नकारात्मक मूल्य अस्थिरता आघातों (असममित प्रभाव) के महत्वपूर्ण विभेदक प्रभाव का कोई साक्ष्य प्राप्त नहीं हुआ है। विस्तार से पढ़ने के लिए कृपया यहाँ क्लिक करें।

आईएनआर के अंतर्राष्ट्रीयकरण संबंधी रिपोर्ट

रिज़र्व बैंक ने 5 जुलाई 2023 को आईएनआर के अंतर्राष्ट्रीयकरण संबंधी अंतर-विभागीय समूह (आईडीजी) की रिपोर्ट अपनी वेबसाइट पर जारी की। आईडीजी का उद्देश्य अंतरराष्ट्रीय मुद्रा के रूप में भारतीय रुपये की मौजूदा स्थिति की समीक्षा करना और भारतीय रुपये के अंतर्राष्ट्रीयकरण के लिए एक रोड मैप तैयार करना था। आईडीजी के विचारार्थ विषय निम्नानुसार थीं–

i) चालू और पूंजी खाता लेनदेन के लिए आईएनआर के उपयोग के लिए मौजूदा ढांचे की समीक्षा करना और उनके वर्तमान स्तरों का आकलन करना;

ii) गैर-निवासियों के बीच लेनदेन के लिए भारतीय रुपये के उपयोग की मौजूदा स्थिति और इस संबंध में अपतटीय बाजारों की भूमिका की समीक्षा करना;

iii) पूंजी खाता उदारीकरण की वांछनीय डिग्री के अनुरूप उपायों का प्रस्ताव करना, व्यापार और वित्तीय लेनदेन चालान और मूल्यवर्ग के लिए आईएनआर के उपयोग हेतु प्रोत्साहन देना, आईएनआर चालान व्यापार पर एडी बैंकों से प्राप्त आंकड़ों का विश्लेषण करने के बाद विदेशी मुद्रा हस्तक्षेप के लिए आधिकारिक आरक्षित निधि और वाहन मुद्रा;

iv) निवासियों और गैर-निवासियों दोनों के लिए आसान पहुंच के साथ हेजिंग उत्पादों की विस्तृत शृंखला, कुशल बैंकिंग प्रणाली और विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचे की उपलब्धता के साथ बाजार की ताकतों और गहन तथा तरल बाजार द्वारा निर्धारित भारतीय रुपये की विनिमय दर में अधिक स्थिरता लाने के उपायों का प्रस्ताव करना;

v) आईएनआर के अंतर्राष्ट्रीयकरण से उत्पन्न होने वाली समस्याओं, यदि कोई हो, के समाधान के उपायों की सिफारिश करना; और

vi) कोई अन्य मुद्दा, जिसे आईडीजी, इस विषय के लिए प्रासंगिक मानता है।

आईडीजी ने अब अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है जिसमें सिफारिशों का अंतिम सेट शामिल है। विस्तार से पढ़ने के लिए कृपया यहाँ क्लिक करें।

VII. सर्वेक्षण

त्रैमासिक औद्योगिक संभावना सर्वेक्षण

भारतीय रिज़र्व बैंक ने 21 जुलाई 2023 को जुलाई-सितंबर 2023 की संदर्भ अवधि के लिए भारतीय विनिर्माण क्षेत्र के त्रैमासिक औद्योगिक संभावना सर्वेक्षण (आईओएस) के 103वें दौर की शुरुआत की है। इस सर्वेक्षण में वर्तमान तिमाही (2023-24 की दूसरी तिमाही) के लिए कारोबारी मनोभाव और आगामी तिमाही (2023-24 की तीसरी तिमाही) के लिए प्रत्याशाओं का आकलन किया जाता है, जो मांग की स्थितियों, वित्तीय स्थितियों, रोजगार की स्थितियों तथा मूल्य स्थिति से संबंधित संकेतकों के समूह पर गुणवत्तापूर्ण प्रत्युत्तरों पर आधारित है। इसमें बाद की दो तिमाहियों (2023-24 की चौथी तिमाही और 2024-25 की पहली तिमाही) के लिए प्रमुख मापदंडों से संबंधित संभावना को भी शामिल किया गया है। मैसर्स जेनेसिस मैनेजमेंट एंड मार्केट रिसर्च प्रा. लि. को भारतीय रिज़र्व बैंक की ओर से जुलाई-सितंबर 2023 तिमाही का सर्वेक्षण करने के लिए प्राधिकृत किया गया है। विस्तार से पढ़ने के लिए कृपया यहाँ क्लिक करें।

बैंकिंग सेवाओं में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार सर्वेक्षण

भारतीय रिज़र्व बैंक ने 21 जुलाई 2023 को बैंकिंग सेवाओं में अंतरराष्ट्रीय व्यापार (आईटीबीएस) पर सर्वेक्षण के 2022-23 दौर की शुरूआत की। वर्ष 2006-07 से प्रतिवर्ष आयोजित किया जाने वाला सर्वेक्षण, भारतीय बैंकों की विदेशों में कार्यरत शाखाओं/ सहायक संस्थाओं/ संयुक्त उद्यमों और विदेशी बैंकों की भारत में कार्यरत शाखाओं/ सहायक संस्थाओं द्वारा प्रदान की गई वित्तीय सेवाओं के बारे में जानकारी प्रदान करता है, जो ग्राहकों से वसूल किए जाने वाले सुस्पष्ट/ अंतर्निहित शुल्क/ कमीशन पर आधारित है।

वर्ष 2022-23 के दौर के लिए सर्वेक्षण अनुसूची विदेशों में कार्यरत भारतीय बैंकों की शाखाओं/ सहायक संस्थाओं/ संयुक्त उद्यम और भारत में कार्यरत विदेशी बैंकों की शाखाओं/ सहायक संस्थाओं द्वारा भरा जाना आवश्यक है। इस सर्वेक्षण अनुसूची का सॉफ्ट फॉर्म भारतीय रिज़र्व बैंक की वेबसाइट पर उपलब्ध है। विस्तार से पढ़ने के लिये कृपया यहाँ क्लिक करें।

सेवाएं और मूलभूत सुविधा संभावना सर्वेक्षण (एसआईओएस)

भारतीय रिज़र्व बैंक ने 21 जुलाई 2023 को जुलाई-सितंबर 2023 की संदर्भ अवधि के लिए तिमाही सेवाएं और मूलभूत सुविधा संभावना सर्वेक्षण (एसआईओएस) के 38वें दौर की शुरुआत की। यह सर्वेक्षण मांग स्थितियों, वित्तीय स्थितियों, रोजगार स्थितियों तथा मूल्य स्थिति से संबंधित संकेतकों के समूह पर गुणवत्तापूर्ण प्रत्युत्तरों के आधार पर भारत में सेवाओं और मूलभूत सुविधा क्षेत्र की चुनिंदा कंपनियों की वर्तमान तिमाही (2023-24 की दूसरी तिमाही) के लिए कारोबारी स्थिति तथा आगामी तिमाही (2023-24 की तीसरी तिमाही) के लिए उनकी संभावना का आकलन करता है। इस सर्वेक्षण दौर में बाद की दो तिमाहियों (2023-24 की चौथी तिमाही और 2024-25 की पहली तिमाही) के लिए प्रमुख मापदंडों पर संभावना को भी शामिल किया गया है। मेसर्स जेनेसिस मैनेजमेंट एंड मार्केट रिसर्च प्राइवेट लिमिटेड को जुलाई-सितंबर 2023 तिमाही के लिए सर्वेक्षण करने हेतु भारतीय रिज़र्व बैंक की ओर से प्राधिकृत किया गया है। विस्तार से पढ़ने के लिए कृपया यहाँ क्लिक करें।

VIII. प्रकाशन

आरबीआई बुलेटिन

रिज़र्व बैंक ने 17 जुलाई 2023 को अपने मासिक बुलेटिन का जुलाई 2023 अंक जारी किया। बुलेटिन में तीन भाषण, छ:आलेख और वर्तमान सांख्यिकी शामिल हैं।

तीन भाषण निम्नानुसार हैं:

i) श्री शक्तिकान्त दास, गवर्नर भारतीय रिज़र्व बैंक ने 30 जून 2023 को मुंबई में भारतीय रिज़र्व बैंक के सांख्यिकी और सूचना प्रबंधन विभाग द्वारा आयोजित 17वें सांख्यिकी दिवस सम्मेलन में उद्घाटन भाषण दिया।

ii) डॉ. माइकल देवव्रत पात्र, उप गवर्नर, भारतीय रिज़र्व बैंक ने 30 जून 2023 को मुंबई में भारतीय रिज़र्व बैंक के सांख्यिकी और सूचना प्रबंध विभाग द्वारा आयोजित 17वें सांख्यिकी दिवस सम्मेलन में 'मौद्रिक नीति के निर्धारण को आकार देने वाली सांख्यिकी' विषय पर भाषण दिया।

iii) श्री टी. रबी शंकर, उप गवर्नर, भारतीय रिजर्व बैंक ने 7 जुलाई 2023 को बेंगलुरु में मनीकंट्रोल इंडिया स्टार्टअप कॉन्क्लेव में आरबीआई और फिनटेक: आगे की राह विषय पर मुख्य भाषण दिया।

प्रकाशित छह आलेख निम्नानुसार है:

i) अर्थव्यवस्था की स्थिति

मूल जड़ता परंतु नरम पड़ती हेडलाइन मुद्रास्फीति के बीच वैश्विक संवृद्धि की त्वरा अवरुद्ध प्रतीत होती है - विशेष रूप से विनिर्माण और निवेश। हॉकिश नीतिगत रुख की प्रतिक्रिया में भावी ब्याज दरों को लेकर बाजार प्रत्याशाएँ बढ़ गई हैं; इक्विटी की कीमतें कम हो गई हैं; और बॉण्ड प्रतिफल बढ़ गए हैं। भारत में, चक्रवात के कारण वर्षा की कमी तेजी से दूर हो रही है। जून में कुछ क्रमिक नरमी के बावजूद विनिर्माण और सेवा गतिविधियों में विस्तार जारी है। वर्ष 2023-24 की पहली तिमाही में समग्र भुगतान संतुलन में सुधार हुआ; यह दर्शाता है कि वित्त प्रवाह, तिमाही आधार पर फिर से चालू खाते से अधिक हो गया है।

ii) एहतियात संचार का महत्वपूर्ण हिस्सा है

यह आलेख एक दिवसीय सूचकांकित स्वैप दरों का उपयोग कर, एक ऑटो रिग्रेसिव कंडिशनल हेटेरोसेडैस्टिक (एआरसीएच) मॉडल के माध्यम से, विशेष रूप से दर-सख्ती अवधि में, भावी संकेत के रूप में मौद्रिक नीति संचार की भूमिका की पड़ताल करता है।

iii) भारत के लिए एक प्रोटोटाइप डायनेमिक स्टोचैस्टिक जनरल इक्विलिब्रियम मॉडल

यह आलेख भारत के लिए एक प्रोटोटाइप डायनेमिक स्टोचैस्टिक जनरल इक्विलिब्रियम (डीएसजीई) मॉडल का अनुमान लगाता है, जो महामारी और यूक्रेन में युद्ध के आघात से पहले और उनके बाद अर्थव्यवस्था में संरचनात्मक परिवर्तनों और मौद्रिक नीति के प्रमुख मानदंडों में बदलाव का आकलन करता है।

iv) सार्वजनिक व्यय और आर्थिक संवृद्धि की गुणवत्ता: उप-राष्ट्रीय स्तर पर एक आनुभविक मूल्यांकन

उत्पादक व्यय के हिस्से को बढ़ाकर सार्वजनिक व्यय की गुणवत्ता में निरंतर सुधार, संवृद्धि का समर्थन करने में अनुकूल भूमिका निभा सकता है। यह आलेख 2005-06 से 2019-20 की अवधि में 14 प्रमुख भारतीय राज्यों से जुड़े सरकारी व्यय की गुणवत्ता का एक समग्र सूचकांक प्राप्त करने के लिए डायनेमिक फैक्टर मॉडल का उपयोग करता है और एक सामान्य न्यूनतम वर्ग (ओएलएस) फ्रेमवर्क में सकल राज्य देशी उत्पाद (जीएसडीपी) वृद्धि के साथ इसके संबंधों की पड़ताल करता है।

v) भारत @ 100

यह आलेख भारत को 2047-48 तक एक विकसित (उच्च आय वाला) देश बनने के लिए एक सांकेतिक रोडमैप प्रदान करता है।

vi) भारतीय रिज़र्व बैंक के इतिहास के परिप्रेक्ष्य

यह आलेख पांच खंडों में रिज़र्व बैंक के इतिहास के हाल ही में जारी 1997-2008 की अवधि को शामिल करने वाले पांचवें खंड के माध्यम से रिज़र्व बैंक के इतिहास का विहंगम दृश्य प्रस्तुत करता है। विस्तार से पढ़ने के लिए कृपया यहाँ क्लिक करें।

IX. जारी आकड़े

जुलाई 2023 माह के दौरान रिज़र्व बैंक द्वारा जारी महत्वपूर्ण आंकड़े निम्नानुसार हैं:

क्रम सं.	शीर्षक
1	भारत में अनुसूचित बैंकों की स्थिति का विवरण
2	14 जुलाई 2023 को समाप्त पखवाड़े के लिए मुद्रा आपूर्ति
3	भारतीय रिज़र्व बैंक सर्वेक्षण
4	वाणिज्यिक बैंक सर्वेक्षण
5	उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (आधार: 2012=100)
6	केंद्र सरकार लेखा एक नज़र में

योगेश दयाल द्वारा भारतीय रिज़र्व बैंक, संचार विभाग, केंद्रीय कार्यालय, शहीद भगत सिंह मार्ग, मुंबई - 400 001 के लिए संपादित और प्रकाशित। मोनेटरी एंड क्रेडिट इन्फॉर्मेशन रीव्यू https://mcir.rbi.org.in पर उपलब्ध है।